International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 15 Issue 10 || October 2026 || PP. 13-27

लोकतंत्र की नई पीढ़ी: नेपाल की 2025 की राजनीतिक उथल-पुथल में जेन Z की निर्णायक भूमिका, उसके कारण और सरकार के पतन तक पहुँचे परिणाम

डॉ. हरी राम एवं डॉ. आशीष कुमार लाल*
राजनीति विज्ञान विभाग, ए.एन.डी. किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बभनान, गोंडा, उत्तर प्रदेश
**राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एल.के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश*

सार (Abstract)

*यह अध्ययन **नेपाल** में वर्ष 2025 के दौरान घटित राजनीतिक उथल-पुथल में **जेनरेशन Z (Gen Z)** की भूमिका का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध का केंद्रीय उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार आर्थिक असुरक्षा, बढ़ती बेरोज़गारी, शासन-विफलता, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, तथा डिजिटल मीडिया के तीव्र प्रसार ने नेपाली जेन Z को संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया। अध्ययन में यह प्रतिपादित किया गया है कि 2025 के जन-आंदोलन केवल तात्कालिक आक्रोश की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे दीर्घकालिक संरचनात्मक समस्याओं, पीढ़ीगत हाशियाकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास-ह्रास का परिणाम थे। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने इन आंदोलनों को विकेन्द्रित नेतृत्व, तीव्र जन-लामबंदी और वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श प्रदान किया, जिससे पारंपरिक राजनीतिक दलों और राज्य तंत्र पर अभूतपूर्व दबाव बना। परिणामस्वरूप, सरकार का पतन केवल संसदीय गणित का नहीं, बल्कि युवा-नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक दबाव का प्रतिफल सिद्ध हुआ। यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि नेपाल का 2025 का अनुभव विकासशील लोकतंत्रों में जेन Z की राजनीतिक शक्ति, डिजिटल नागरिकता और लोकतंत्र के बदलते स्वरूप को समझने के लिए एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है।*

मुख्य शब्द : *Gen Z, नेपाल, युवा राजनीति, डिजिटल आंदोलन, राजनीतिक अस्थिरता, लोकतांत्रिक परिवर्तन, 2025 विरोध आंदोलन*

1. प्रस्तावना (Introduction)

इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक विश्व-राजनीति के इतिहास में एक ऐसे कालखंड के रूप में उभर रहा है जहाँ **युवा पीढ़ी**, विशेषकर **जेनरेशन Z (Gen Z)**, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की सबसे प्रभावशाली शक्ति बनकर सामने आई है। यह पीढ़ी न केवल जनसांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैचारिक, तकनीकी और नैतिक स्तर पर भी राजनीति के पारंपरिक स्वरूप को चुनौती दे रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, वैश्विक सूचना प्रवाह और नेटवर्क-आधारित संचार ने जेन Z को अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना प्रदान की है। परिणामस्वरूप, यह पीढ़ी सत्ता, शासन और लोकतंत्र को केवल स्वीकार करने वाली नहीं, बल्कि उन्हें पुनर्परिभाषित करने वाली पीढ़ी बन गई है। दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा है और जहाँ लोकतंत्र निरंतर संक्रमण की अवस्था में है, वहाँ जेन Z की भूमिका और भी अधिक निर्णायक हो जाती है। इसी संदर्भ में **नेपाल** का 2025 का राजनीतिक upheaval एक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभरता है। नेपाल में घटित यह राजनीतिक उथल-पुथल केवल एक सरकार के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि यह युवा असंतोष, डिजिटल सक्रियता, और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के सामूहिक विस्फोट का प्रतीक है। नेपाल का आधुनिक राजनीतिक इतिहास स्वयं में संघर्षों और संक्रमणों से भरा रहा है।

2008 में राजशाही की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना के बाद यह अपेक्षा की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली देश को स्थिरता, समावेशिता और विकास की ओर ले जाएगी। किंतु वास्तविकता यह रही कि बीते डेढ़ दशकों में नेपाल निरंतर राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर गठबंधन सरकारों, नीति-निर्माण में गतिरोध और संस्थागत अविश्वास से जूझता रहा। इस लंबे संक्रमण काल का सबसे गहरा प्रभाव उस पीढ़ी पर पड़ा जो इसी दौर में किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रही थी—अर्थात जेन Z। जेन Z का राजनीतिक समाजीकरण ऐसे समय में हुआ जब लोकतंत्र से अपेक्षाएँ तो बहुत थीं, परंतु उनके जीवन में अवसर सीमित थे। शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद रोजगार के अवसरों की कमी, बढ़ती महँगाई, विदेश पलायन की मजबूरी, और भ्रष्टाचार से ग्रस्त प्रशासन ने इस पीढ़ी में यह भावना पैदा की कि राजनीतिक व्यवस्था उनके भविष्य को सुरक्षित करने में असमर्थ है। इस प्रकार, जेन Z का असंतोष केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि ठोस सामाजिक-आर्थिक अनुभवों पर आधारित था।

2025 में नेपाल में जो राजनीतिक आंदोलन उभरे, वे अचानक नहीं थे। वे वर्षों से संचित असंतोष, हताशा और अपेक्षाभंग का परिणाम थे। इन आंदोलनों की विशिष्टता यह थी कि उनका नेतृत्व किसी एक राजनीतिक दल, विचारधारा या करिश्माई नेता के हाथ में नहीं था। इसके विपरीत, यह एक **विकेन्द्रित, नेटवर्क-आधारित और डिजिटल रूप से संगठित जन-आंदोलन** था, जिसमें जेन Z की भूमिका केंद्रीय थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से युवाओं ने न केवल अपनी शिकायतें साझा कीं, बल्कि वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श भी निर्मित किया। यह भी उल्लेखनीय है कि जेन Z के आंदोलन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं थे। इनमें **सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और पहचान-आधारित अधिकारों** जैसे व्यापक मुद्दे शामिल थे। इस प्रकार, 2025 का नेपाली आंदोलन एक बहुआयामी सामाजिक-राजनीतिक घटना था, जिसने यह स्पष्ट किया कि जेन Z लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं मानती, बल्कि उसे एक निरंतर सहभागी प्रक्रिया के रूप में देखती है। नेपाल की 2025 की राजनीतिक उथल-पुथल को इस दृष्टि से भी समझना आवश्यक है कि यह डिजिटल युग की राजनीति का एक प्रतिनिधि उदाहरण है। जेन Z ने पारंपरिक राजनीतिक संस्थानों और मीडिया के समानांतर एक नया "डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र" निर्मित किया, जहाँ विमर्श, आलोचना और संगठन एक साथ संभव हुए। लाइव स्ट्रीमिंग, हैशटैग अभियानों, ऑनलाइन याचिकाओं और नागरिक पत्रकारिता ने सत्ता और समाज के बीच की दूरी को कम कर दिया। इससे सरकार पर जन-दबाव तीव्र हुआ और अंततः राजनीतिक संकट ने निर्णायक रूप ले लिया।

यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र में परिवर्तन केवल संसद या चुनाव के माध्यम से ही नहीं, बल्कि संगठित नागरिक दबाव और युवा सहभागिता के माध्यम से भी संभव है। जेन Z के आंदोलनों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या पारंपरिक राजनीतिक दल और संस्थाएँ नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को समझने और समाहित करने में सक्षम हैं। सरकार का पतन इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर प्रतीत होता है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य नेपाल की 2025 की राजनीतिक उथल-पुथल को केवल एक राजनीतिक संकट के रूप में नहीं, बल्कि एक **पीढ़ीगत लोकतांत्रिक हस्तक्षेप** के रूप में समझना है। यह प्रस्तावना उस व्यापक पृष्ठभूमि को रेखांकित करती है जिसमें आर्थिक असमानता, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, शासन-विफलता, जलवायु संबंधी चिंताएँ, पहचान-आधारित राजनीति और डिजिटल मीडिया के परस्पर संबंधों ने युवा-आधारित विरोध को जन्म दिया। इन सभी कारकों ने मिलकर जेन Z को एक ऐसी सामूहिक शक्ति में परिवर्तित किया, जिसने न केवल सरकार को चुनौती दी, बल्कि लोकतंत्र के स्वरूप पर भी पुनर्विचार को अनिवार्य बना दिया। इस प्रकार, नेपाल का 2025 का अनुभव यह संकेत देता है कि इक्कीसवीं सदी की राजनीति में जेन Z की भूमिका को नज़रअंदाज़

करना अब संभव नहीं है। यह पीढ़ी न तो निष्क्रिय है और न ही केवल भविष्य की राजनीति तक सीमित है। वह वर्तमान की राजनीति को दिशा देने वाली एक सशक्त शक्ति है। इस अध्ययन की प्रस्तावना इसी बिंदु को रेखांकित करते हुए आगे के विश्लेषण के लिए वैचारिक आधार प्रस्तुत करती है, जहाँ जेन Z की भूमिका, उसके कारणों और उसके दूरगामी परिणामों की गहन विवेचना की जाएगी।

2. जेन Z: अवधारणा और वैश्विक संदर्भ

जेनरेशन Z, जिसे सामान्यतः 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी के रूप में परिभाषित किया जाता है, इक्कीसवीं सदी की वह पहली पीढ़ी है जिसने जन्म से ही डिजिटल तकनीकों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा पाया है। यह पीढ़ी इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक सूचना नेटवर्क के बीच पली-बढ़ी है, जिसके कारण इसका सोचने, सीखने, संवाद करने और राजनीति को समझने का ढंग पूर्ववर्ती पीढ़ियों से मूलतः भिन्न है। जेन Z के लिए सूचना कोई दुर्लभ संसाधन नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है, जिसे वह न केवल उपभोग करती है बल्कि उसका विश्लेषण, पुनर्प्रस्तुतीकरण और आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करती है। यही कारण है कि इस पीढ़ी को "डिजिटल-नेटिव" कहा जाता है, जो तकनीक का उपयोग मात्र साधन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम के रूप में करती है।

वैश्विक संदर्भ में जेन Z की पहचान केवल उसकी आयु-सीमा या तकनीकी दक्षता से नहीं होती, बल्कि उसकी विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक चेतना से होती है। यह पीढ़ी सत्ता, परंपरा और स्थापित संस्थाओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करती, बल्कि उन पर प्रश्न उठाने को अपना लोकतांत्रिक अधिकार मानती है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जेन Z ने विश्व को आर्थिक मंदी, जलवायु संकट, वैश्विक महामारी, युद्ध, प्रवासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण जैसी चुनौतियों से जूझते हुए देखा है। इन अनुभवों ने इस पीढ़ी के भीतर असुरक्षा के साथ-साथ परिवर्तन की तीव्र आकांक्षा को भी जन्म दिया है। परिणामस्वरूप, जेन Z राजनीति को केवल सत्ता-प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिक उत्तरदायित्व और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों के रूप में देखती है। सूचना-साक्षरता जेन Z की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह पीढ़ी पारंपरिक मीडिया पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहती, बल्कि वैकल्पिक डिजिटल स्रोतों से सूचनाएँ प्राप्त करती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करती है और फर्जी खबरों तथा आधिकारिक नैरेटिव के बीच अंतर करना सीखती है। त्वरित संचार के साधनों—जैसे सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और ऑनलाइन मंचों—ने जेन Z को तत्काल प्रतिक्रिया देने और सामूहिक विमर्श में भाग लेने की क्षमता प्रदान की है। यही कारण है कि यह पीढ़ी राजनीतिक घटनाओं पर केवल प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि स्वयं विमर्श की दिशा भी तय करती है। जेन Z की एक अन्य वैश्विक विशेषता है समावेशन और सामाजिक न्याय के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता। नस्ल, जाति, वर्ग, लिंग, लैंगिक पहचान और धार्मिक विविधता जैसे मुद्दे इस पीढ़ी के राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में हैं। यह पीढ़ी असमानता को केवल आर्थिक समस्या नहीं मानती, बल्कि उसे संरचनात्मक अन्याय के रूप में देखती है, जिसे चुनौती देना आवश्यक है। इसी प्रकार, पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन जेन Z के लिए भविष्य का प्रश्न नहीं, बल्कि वर्तमान का संकट है। इसलिए विश्व के विभिन्न हिस्सों में जलवायु आंदोलनों, छात्र आंदोलनों और सामाजिक न्याय अभियानों में जेन Z की सक्रिय भागीदारी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

राजनीतिक संगठन के संदर्भ में जेन Z पारंपरिक, पदानुक्रमित और नेतृत्व-केंद्रित संरचनाओं की बजाय नेटवर्क-आधारित और क्षैतिज संगठन को प्राथमिकता देती है। इस पीढ़ी के आंदोलन अक्सर विकेन्द्रित होते हैं, जहाँ कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं होता, बल्कि अनेक सक्रिय समूह और व्यक्ति मिलकर सामूहिक कार्रवाई करते हैं। यह संरचना आंदोलन को लचीला,

अनुकूलनशील और व्यापक बनाती है, साथ ही सत्ता के दमनात्मक उपायों के प्रति उसे अधिक प्रतिरोधी भी बनाती है। वैश्विक स्तर पर यह प्रवृत्ति विभिन्न छात्र आंदोलनों, लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों और डिजिटल अभियानों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेपाल के संदर्भ में जेन Z की अवधारणा और भूमिका को समझना और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ इस पीढ़ी का राजनीतिक समाजीकरण एक लंबे और जटिल संक्रमण काल में हुआ है। 2008 में राजशाही के अंत और गणतंत्र की स्थापना के बाद नेपाल ने संविधान-निर्माण, संघीय ढाँचे के कार्यान्वयन और नई राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया देखी। किंतु यह प्रक्रिया बार-बार सरकारों के गिरने, गठबंधन राजनीति की अस्थिरता और नीति-निर्माण में निरंतर विलंब से प्रभावित रही। जेन Z ने अपने बचपन और किशोरावस्था में लोकतंत्र के वादों और वास्तविकताओं के बीच के इस अंतर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। नेपाल में जेन Z का राजनीतिक समाजीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहाँ संस्थागत राजनीति के प्रति भरोसा लगातार कमजोर होता गया। राजनीतिक दलों पर अवसरवाद, भ्रष्टाचार और युवाओं की उपेक्षा के आरोप आम हो गए। परिणामस्वरूप, जेन Z के भीतर यह भावना विकसित हुई कि पारंपरिक राजनीतिक संस्थाएँ उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं। इस अविश्वास ने उन्हें प्रत्यक्ष भागीदारी, सड़क-आधारित आंदोलनों और डिजिटल सक्रियता की ओर प्रेरित किया। उनके लिए राजनीति केवल मतदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक निरंतर हस्तक्षेप और निगरानी की प्रक्रिया बन गई।

नेपाल की जेन Z वैश्विक जेन Z प्रवृत्तियों से गहराई से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया और वैश्विक डिजिटल संस्कृति के माध्यम से नेपाली युवाओं ने अन्य देशों के आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक प्रयोगों को देखा और उनसे प्रेरणा ली। इससे उनके भीतर यह विश्वास मजबूत हुआ कि संगठित युवा शक्ति सत्ता-संतुलन को बदल सकती है। साथ ही, स्थानीय संदर्भ—जैसे बेरोज़गारी, विदेश पलायन, शिक्षा और अवसरों की कमी—ने इस वैश्विक चेतना को स्थानीय असंतोष से जोड़ दिया। इस प्रकार, जेन Z को केवल एक आयु-आधारित श्रेणी के रूप में समझना अपर्याप्त होगा। यह एक ऐसी पीढ़ी है जो वैश्विक अनुभवों और स्थानीय वास्तविकताओं के संगम से निर्मित हुई है। नेपाल में जेन Z की भूमिका इसी संगम का परिणाम है, जहाँ डिजिटल-साक्षरता, सामाजिक न्याय की आकांक्षा, पर्यावरणीय चेतना और संस्थागत राजनीति के प्रति अविश्वास ने मिलकर एक नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। यही चेतना 2025 में नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल की आधारशिला बनी। अतः जेन Z की अवधारणा और वैश्विक संदर्भ को समझे बिना नेपाल के 2025 के आंदोलनों का विश्लेषण अधूरा रहेगा। यह पीढ़ी न केवल वैश्विक रुझानों की वाहक है, बल्कि उन्हें स्थानीय संदर्भों में रूपांतरित करने की क्षमता भी रखती है। नेपाल की जेन Z इसी क्षमता के साथ उभरी—एक ऐसी पीढ़ी के रूप में जिसने परंपरागत राजनीति को चुनौती दी और लोकतंत्र को नए अर्थ और नई दिशा देने का प्रयास किया।

3. नेपाल का राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य: 2008–2024

वर्ष 2008 नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज है, जब सदियों पुरानी राजशाही व्यवस्था का अंत हुआ और देश ने स्वयं को एक गणतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित किया। यह परिवर्तन केवल सत्ता-संरचना का परिवर्तन नहीं था, बल्कि इससे नेपाल के सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक जीवन में गहरे परिवर्तन की अपेक्षा की गई थी। गणतंत्र की स्थापना के साथ ही समावेशी लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समान अवसर और स्थायी विकास जैसे आदर्शों को साकार करने का वादा किया गया। किंतु 2008 के बाद का कालखंड यह दर्शाता है कि राजनीतिक आदर्शों और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच एक गहरी खाई बनी रही, जिसने विशेष रूप से युवाओं और जेन Z पीढ़ी को सबसे अधिक प्रभावित

किया। गणतंत्र की स्थापना के पश्चात नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद की जा रही थी, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत रही। 2008 से 2024 तक नेपाल ने बार-बार सरकारों का बदलना, कमजोर गठबंधन राजनीति, और सत्ता-साझेदारी के अस्थायी समझौतों का दौर देखा। विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता में तो आए, परंतु वे दीर्घकालिक नीतिगत दृष्टि विकसित करने में असफल रहे। सरकारों का अल्पकालिक होना, मंत्रिमंडलों का बार-बार पुनर्गठन और राजनीतिक टकराव ने प्रशासनिक क्षमता को कमजोर कर दिया। इसका सीधा प्रभाव शासन की गुणवत्ता और सार्वजनिक विश्वास पर पड़ा। 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया, जिसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा गया। इस संविधान ने नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया और समावेशन, अधिकारों की गारंटी तथा विकेन्द्रीकरण पर बल दिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लंबे संघर्ष और आंदोलन शामिल थे, जिससे यह अपेक्षा बनी कि नया संवैधानिक ढाँचा राजनीतिक अस्थिरता को कम करेगा। परंतु संविधान लागू होने के बाद भी संघीय ढाँचे का प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना रहा। केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का अस्पष्ट विभाजन, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक अनुभव का अभाव संघीय व्यवस्था को कमजोर करता रहा।

राजनीतिक अस्थिरता के साथ-साथ नीतिगत जड़ता नेपाल के राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य की एक प्रमुख विशेषता बन गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता थी, परंतु सरकारें अक्सर तात्कालिक राजनीतिक लाभों में उलझी रहीं। योजनाएँ घोषित तो की गईं, परंतु उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि राजनीतिक नेतृत्व नीति-निर्माण से अधिक सत्ता-संतुलन और गठबंधन प्रबंधन में व्यस्त है। इस पूरे दौर में भ्रष्टाचार के आरोप लगातार नेपाली राजनीति का हिस्सा बने रहे। सार्वजनिक परियोजनाओं, नियुक्तियों और संसाधनों के वितरण में भ्रष्टाचार की चर्चाओं ने जनता के विश्वास को गहराई से चोट पहुँचाई। युवाओं के लिए यह अनुभव विशेष रूप से निराशाजनक था, क्योंकि वे लोकतंत्र को पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर देखते थे। जब लोकतांत्रिक संस्थाएँ ही संदेह के घेरे में आने लगीं, तो युवाओं के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठा कि क्या यह व्यवस्था वास्तव में उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत विफलताओं का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिला। नेपाल में युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण और स्थायी रोजगार के अवसर सीमित रहे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बड़ी संख्या में युवाओं को या तो बेरोजगारी का सामना करना पड़ा या अल्पवेतन और असुरक्षित नौकरियों में काम करना पड़ा। उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो सके, जबकि कृषि क्षेत्र में आय की अनिश्चितता बनी रही। इस स्थिति में युवाओं के लिए लोकतंत्र का वादा अधूरा प्रतीत होने लगा। शिक्षा-प्रणाली और श्रम-बाज़ार के बीच बढ़ता असंतुलन भी इस कालखंड की एक गंभीर समस्या रही। शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले युवाओं के कौशल और श्रम-बाज़ार की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच तालमेल की कमी स्पष्ट थी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम अक्सर व्यावहारिक आवश्यकताओं से कटे हुए थे, जिससे डिग्रीधारी युवाओं की रोजगार-क्षमता सीमित रह गई। यह स्थिति जेन Z के लिए विशेष रूप से पीड़ादायक थी, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता का माध्यम माना था।

ग्रामीण-शहरी असमानता नेपाल के राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य की एक स्थायी विशेषता बनी रही। शहरी क्षेत्रों में सीमित अवसर, बुनियादी सुविधाएँ और डिजिटल पहुँच अपेक्षाकृत बेहतर थीं, जबकि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर सीमित रहे। इस असमानता ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया और यह भावना मजबूत की कि विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो रहा है। जेन Z, जो डिजिटल माध्यमों के कारण इन असमानताओं

को अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रही थी, इस स्थिति से गहराई से प्रभावित हुई। इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप विदेश प्रवासन में तीव्र वृद्धि हुई। 2008 से 2024 के बीच नेपाल से बड़ी संख्या में युवा रोज़गार की तलाश में खाड़ी देशों, मलेशिया और अन्य क्षेत्रों की ओर गए। यह प्रवासन केवल आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह देश की राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं पर अविश्वास का संकेत भी था। जेन Z के लिए विदेश जाना अक्सर मजबूरी बन गया, न कि विकल्प। इससे परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि युवा कार्यबल का बड़ा हिस्सा देश से बाहर चला गया। इन परिस्थितियों में जेन Z ने स्वयं को धीरे-धीरे एक "लॉस्ट जेनरेशन" के रूप में देखना शुरू किया। यह वह पीढ़ी थी जिसने लोकतंत्र के आदर्श, अधिकारों की भाषा और विकास के वादे तो सुने, परंतु अपने जीवन में उनके ठोस परिणाम कम ही देखे। लोकतंत्र उनके लिए एक सैद्धांतिक अवधारणा बनकर रह गया, जो व्यवहार में अवसरों और सुरक्षा में परिवर्तित नहीं हो सका। यह अनुभूति केवल व्यक्तिगत निराशा तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामूहिक चेतना का रूप लेने लगी। इस "लॉस्ट जेनरेशन" की भावना ने जेन Z को पारंपरिक राजनीति से अलग सोचने के लिए प्रेरित किया। वे राजनीतिक दलों, नेताओं और संस्थानों को उसी तरह नहीं देखने लगे जैसे पिछली पीढ़ियाँ देखती थीं। उनके लिए सवाल यह नहीं था कि कौन सा दल सत्ता में है, बल्कि यह था कि सत्ता उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। इसी दृष्टिकोण ने आगे चलकर युवाओं को प्रत्यक्ष भागीदारी, विरोध और वैकल्पिक राजनीतिक अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख किया। अतः 2008 से 2024 तक का नेपाल का राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य केवल संक्रमण और अस्थिरता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पृष्ठभूमि को भी निर्मित करता है, जिसमें जेन Z का असंतोष, आकांक्षा और राजनीतिक सक्रियता आकार लेती है। गणतंत्र, संघीयता और संविधान जैसे ऐतिहासिक परिवर्तनों के बावजूद यदि अवसरों की कमी, असमानता और शासन-विफलता बनी रहती है, तो युवा पीढ़ी का व्यवस्था पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक हो जाता है। यही पृष्ठभूमि 2025 में जेन Z के नेतृत्व में उभरे आंदोलनों की वैचारिक और सामाजिक नींव बनी, जिसने नेपाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया।

4. 2025 की पृष्ठभूमि: असंतोष का संचय

नेपाल में 2025 में घटित राजनीतिक उथल-पुथल को यदि एक अचानक विस्फोट के रूप में देखा जाए, तो यह विश्लेषण अधूरा रहेगा। वास्तव में यह upheaval वर्षों से धीरे-धीरे संचित होते असंतोष, निराशा और अपेक्षाभंग का परिणाम था। 2023–24 के दौरान यह असंतोष एक निर्णायक स्तर तक पहुँच गया, जहाँ आर्थिक दबाव, राजनीतिक अविश्वास, सामाजिक-सांस्कृतिक असमानताएँ और डिजिटल माध्यमों की सक्रियता एक-दूसरे से जुड़कर एक व्यापक जन-आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने लगीं। इस कालखंड में जेन Z ने स्वयं को केवल समस्याओं का शिकार नहीं, बल्कि परिवर्तन के वाहक के रूप में देखना शुरू किया। यही संचय 2025 में संगठित विरोध और अंततः सरकार के पतन में परिवर्तित हुआ।

4.1 आर्थिक कारण

2023–24 के दौरान नेपाल की अर्थव्यवस्था गंभीर दबाव में रही। महँगाई में निरंतर वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता और आय के सीमित स्रोतों ने आम नागरिकों के जीवन को कठिन बना दिया। युवाओं के लिए यह स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनके सामने स्थायी और सम्मानजनक रोज़गार के अवसर सीमित थे। निजी क्षेत्र में रोजगार असुरक्षित था, जबकि सरकारी नौकरियों की संख्या अत्यंत सीमित और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी। इस असंतुलन ने युवाओं में यह भावना पैदा की कि आर्थिक व्यवस्था उनके श्रम और शिक्षा का उचित प्रतिफल नहीं दे पा रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की बेरोज़गारी ने असंतोष को और तीव्र किया। विश्वविद्यालयों और

तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले स्नातक और परास्नातक युवा स्वयं को अयोग्य नहीं, बल्कि अवसर-वंचित महसूस करने लगे। उनके लिए यह प्रश्न केंद्रीय बन गया कि यदि शिक्षा भी रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती, तो लोकतंत्र का वादा किसके लिए है। यही प्रश्न धीरे-धीरे व्यक्तिगत निराशा से सामूहिक राजनीतिक असंतोष में परिवर्तित हुआ। इन आर्थिक परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम विदेश-प्रवास में तीव्र वृद्धि के रूप में सामने आया। 2023–24 के दौरान बड़ी संख्या में युवा रोज़गार की तलाश में विदेश जाने लगे। यह प्रवासन केवल आर्थिक रणनीति नहीं था, बल्कि यह राज्य की नीतिगत विफलता का संकेत भी बन गया। जब पढ़ा-लिखा युवा देश छोड़ने को मजबूर हो, तो "ब्रेन ड्रेन" केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। जेन Z ने इसे राष्ट्रीय भविष्य के लिए खतरे के रूप में देखा और यह प्रश्न उठाया कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो देश के विकास का भार कौन उठाएगा।

4.2 राजनीतिक कारण

आर्थिक असंतोष के समानांतर राजनीतिक कारणों ने भी 2025 की पृष्ठभूमि को आकार दिया। गठबंधन सरकारों की अस्थिरता नेपाल की राजनीति की एक स्थायी विशेषता बन चुकी थी। 2023–24 में सरकारें बनीं और गिरीं, परंतु नीति-निर्माण की प्रक्रिया ठहरी रही। निर्णयों में देरी, घोषणाओं और क्रियान्वयन के बीच की खाई, तथा सत्ता-साझेदारी के निरंतर समझौतों ने जनता के विश्वास को कमजोर किया। युवाओं के लिए यह अनुभव और भी निराशाजनक था, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि राजनीति जनहित से अधिक सत्ता-संतुलन की कला बन गई है। युवा-केंद्रित नीतियों की कमी ने इस अविश्वास को और गहरा किया। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में ठोस और दीर्घकालिक नीतियों का अभाव स्पष्ट था। राजनीतिक दल अपने घोषणापत्रों में युवाओं का उल्लेख तो करते थे, परंतु सत्ता में आने के बाद उनके लिए प्राथमिकताएँ बदल जाती थीं। संसद और राजनीतिक दलों में जेन Z का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य था, जिससे यह धारणा मजबूत हुई कि निर्णय-प्रक्रिया में युवाओं की आवाज़ को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है। इस राजनीतिक हाशियाकरण ने जेन Z को पारंपरिक राजनीति से दूर किया और उन्हें प्रत्यक्ष भागीदारी के वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया। मतदान के माध्यम से परिवर्तन की संभावना उन्हें सीमित प्रतीत होने लगी, क्योंकि सत्ता में आने वाले दलों के व्यवहार में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखता था। परिणामस्वरूप, विरोध, प्रदर्शन और सार्वजनिक दबाव राजनीति में हस्तक्षेप के प्रभावी साधन के रूप में उभरने लगे।

4.3 सामाजिक-सांस्कृतिक कारण

आर्थिक और राजनीतिक कारणों के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों ने भी असंतोष के संचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल एक बहु-जातीय, बहु-भाषाई और सांस्कृतिक रूप से विविध समाज है। लोकतांत्रिक परिवर्तन के बावजूद जातीय, क्षेत्रीय और लैंगिक समानता के प्रश्नों पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। कई समुदायों को यह महसूस होता रहा कि वे सत्ता, संसाधनों और अवसरों के वितरण में पीछे छूट गए हैं। जेन Z, जो अधिक जागरूक और संवेदनशील थी, इन असमानताओं को केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक अन्याय के रूप में देखने लगी। लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा, LGBTQ+ अधिकार और सामाजिक समावेशन जैसे मुद्दे युवाओं के विमर्श के केंद्र में आ गए। यह असंतोष केवल शहरी युवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की जेन Z भी सक्रिय होने लगी। डिजिटल माध्यमों के कारण ग्रामीण युवाओं को भी अपने अनुभव साझा करने और व्यापक आंदोलनों से जुड़ने का मंच मिला। इस सामाजिक-सांस्कृतिक जागरूकता ने जेन Z को पारंपरिक पहचान-आधारित राजनीति से आगे सोचने के लिए प्रेरित किया।

वे केवल अपने समुदाय या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाने लगे। यही कारण है कि 2025 के आंदोलन बहु-आयामी थे और उनमें विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी दिखाई दी।

4.4 डिजिटल कारण

2025 की पृष्ठभूमि को समझने में डिजिटल कारकों की भूमिका केंद्रीय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म—फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और टिकटॉक—ने असंतोष को अभिव्यक्ति, संगठन और दिशा प्रदान की। इन प्लेटफॉर्मों ने जेन Z को विकेन्द्रित नेतृत्व की सुविधा दी, जहाँ किसी एक नेता या संगठन के बिना भी बड़े पैमाने पर लामबंदी संभव हो सकी। हैशटैग अभियानों, वायरल वीडियो और ऑनलाइन चर्चाओं ने मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। डिजिटल माध्यमों ने तेज़ लामबंदी को संभव बनाया। किसी घटना, बयान या नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया कुछ ही घंटों में देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकती थी। साथ ही, नैरेटिव-निर्माण की शक्ति भी युवाओं के हाथ में आ गई। वे पारंपरिक मीडिया पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं अपनी कहानियाँ, अनुभव और विश्लेषण साझा करने लगे। इससे सत्ता की आधिकारिक व्याख्याओं को चुनौती मिली और वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण हुआ। डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने न केवल संगठन और संवाद को सरल बनाया, बल्कि युवाओं को यह विश्वास भी दिया कि वे अकेले नहीं हैं। समान अनुभवों और साझा असंतोष ने एक सामूहिक पहचान को जन्म दिया, जिसने 2025 के आंदोलनों को भावनात्मक और नैतिक शक्ति प्रदान की। इस प्रकार, डिजिटल कारक केवल तकनीकी साधन नहीं रहे, बल्कि वे असंतोष के संचय को राजनीतिक कार्रवाई में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक बन गए। समग्र रूप से देखें तो 2025 की पृष्ठभूमि आर्थिक संकट, राजनीतिक अविश्वास, सामाजिक-सांस्कृतिक असमानताओं और डिजिटल सक्रियता के परस्पर प्रभाव से निर्मित हुई। इन सभी कारकों ने मिलकर जेन Z के भीतर यह भावना उत्पन्न की कि मौजूदा व्यवस्था उनके भविष्य की सुरक्षा करने में असमर्थ है। यही संचय 2025 में संगठित विरोध और निर्णायक राजनीतिक परिवर्तन का आधार बना, जिसने नेपाल की राजनीति को एक नए चरण में प्रवेश करने के लिए विवश कर दिया।

5. जेन Z आंदोलनों की प्रकृति और स्वरूप

नेपाल में 2025 के दौरान उभरे जेन Z आंदोलनों की प्रकृति और स्वरूप पारंपरिक राजनीतिक आंदोलनों से मूलतः भिन्न थे। इन आंदोलनों को अक्सर "नेतृत्व-विहीन" कहकर समझने की कोशिश की गई, किंतु वास्तविकता यह थी कि ये आंदोलन नेतृत्व से रहित नहीं, बल्कि **बहु-केंद्रित (multi-centric)** थे। अर्थात इनमें कोई एक सर्वोच्च नेता या संगठन नहीं था, बल्कि अनेक समूह, नेटवर्क और व्यक्ति मिलकर आंदोलन को दिशा दे रहे थे। यह संरचना जेन Z की उस सोच को प्रतिबिंबित करती है, जो सत्ता और निर्णय-निर्माण को केंद्रीकृत करने के बजाय साझा और क्षैतिज रूप में देखती है। इसी बहु-केंद्रित स्वरूप ने आंदोलनों को लचीला, व्यापक और दमन के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाया। जेन Z आंदोलनों की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वे डिजिटल और भौतिक—दोनों क्षेत्रों में समान रूप से सक्रिय थे। हैशटैग-आधारित ऑनलाइन अभियानों से लेकर सड़कों पर निकलने वाली विशाल रैलियों तक, इन आंदोलनों ने विरोध के विविध रूपों को एक साथ अपनाया। सोशल मीडिया पर चलने वाले अभियानों ने मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया, जबकि ऑफ़लाइन रैलियों और धरनों ने इन मुद्दों को दृश्य और प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाव में परिवर्तित किया। यह दोहरा स्वरूप यह दर्शाता है कि जेन Z डिजिटल सक्रियता को वास्तविक राजनीतिक कार्रवाई का पूरक मानती है, उसका विकल्प नहीं।

इन आंदोलनों का एक और महत्वपूर्ण आयाम उनका **क्रिएटिव विरोध** था। पोस्टर-आर्ट, ग्राफ़िटी, व्यंग्यात्मक कार्टून, संगीत, रैप, कविता और स्ट्रीट-परफॉर्मेंस के माध्यम से युवाओं ने अपनी असहमति व्यक्त की। यह विरोध न केवल नारों और भाषणों तक सीमित था, बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का रूप ले चुका था। रचनात्मकता ने आंदोलनों को आकर्षक, जन-सुलभ और भावनात्मक रूप से प्रभावी बनाया। इससे आम नागरिक, विशेषकर वे लोग जो पारंपरिक राजनीति से दूरी बनाए रखते थे, भी आंदोलनों से जुड़ने लगे। क्रिएटिव विरोध का एक गहरा राजनीतिक अर्थ भी था। यह जेन Z की उस मानसिकता को दर्शाता है जो सत्ता के प्रति भय के बजाय व्यंग्य और आलोचना का सहारा लेती है। पोस्टर और गीतों के माध्यम से सरकार की नीतियों, नेताओं के बयानों और राजनीतिक विफलताओं को चुनौती दी गई। यह प्रतीकात्मक राजनीति थी, जिसने सत्ता के औपचारिक और गंभीर स्वरूप को तोड़कर उसे जन-संवाद के स्तर पर ला दिया। इस प्रकार, रचनात्मकता आंदोलन का केवल सौंदर्य पक्ष नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक शक्ति भी बनी।

जेन Z आंदोलनों की एक अन्य विशिष्ट विशेषता थी उनकी **डेटा-ड्रिवन आलोचना**। पारंपरिक आंदोलनों में जहाँ भावनात्मक अपील और वैचारिक नारे प्रमुख होते थे, वहीं 2025 के आंदोलनों में नीति-विश्लेषण, बजट-तुलना, सरकारी आँकड़ों की समीक्षा और तथ्यों के आधार पर आलोचना देखने को मिली। युवाओं ने सरकारी दस्तावेज़ों, बजट भाषणों और नीतिगत घोषणाओं का विश्लेषण कर यह दिखाया कि वादों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच कितना अंतर है। इससे आंदोलन की वैधता और विश्वसनीयता बढ़ी। डेटा-आधारित आलोचना ने जेन Z को केवल "आक्रोशित युवा" के रूप में प्रस्तुत होने से रोका और उन्हें एक जागरूक, तर्कसंगत और जिम्मेदार नागरिक समूह के रूप में स्थापित किया। जब आंदोलनकारी ठोस आँकड़ों और तुलनाओं के साथ अपनी बात रखते हैं, तो सत्ता के लिए उन्हें नज़रअंदाज़ करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार, जेन Z ने ज्ञान और सूचना को राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित करने का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया।

इन आंदोलनों का स्वरूप **समावेशी एजेंडा** से भी चिह्नित था। 2025 के जेन Z आंदोलनों में महिलाओं, LGBTQ+ समुदाय, आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले युवाओं की सक्रिय भागीदारी दिखाई दी। आंदोलन केवल किसी एक वर्ग या समूह की माँगों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने व्यापक सामाजिक न्याय के प्रश्नों को उठाया। लैंगिक समानता, यौनिक अल्पसंख्यकों के अधिकार, जातीय और क्षेत्रीय समावेशन जैसे मुद्दे आंदोलन के केंद्रीय विमर्श का हिस्सा बने। इस समावेशी स्वरूप ने आंदोलनों को नैतिक बल प्रदान किया। जब विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए युवा एक साझा मंच पर खड़े होते हैं, तो यह संदेश जाता है कि आंदोलन संकीर्ण स्वार्थों के लिए नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन के लिए है। इससे आंदोलन की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ी और सत्ता पर नैतिक दबाव भी गहरा हुआ। यह समावेशन जेन Z की उस वैश्विक चेतना का प्रतिबिंब था, जो विविधता को शक्ति और लोकतंत्र की बुनियाद मानती है। जेन Z आंदोलनों की प्रकृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनका **शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़** होना था। 2025 के अधिकांश आंदोलन अहिंसक रहे, परंतु वे कमजोर या निष्क्रिय नहीं थे। शांतिपूर्ण तरीकों—जैसे धरना, मौन प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन-संवाद—के माध्यम से युवाओं ने अपनी माँगों को स्पष्ट रूप से सामने रखा। अहिंसा ने आंदोलनों को नैतिक उच्चता प्रदान की और राज्य की दमनात्मक कार्रवाइयों को जनमत की दृष्टि में संदिग्ध बना दिया।

इन आंदोलनों का लक्ष्य केवल सत्ता-परिवर्तन नहीं था। यद्यपि सरकार का पतन एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा, परंतु जेन Z की माँगें उससे कहीं व्यापक थीं। उनका मुख्य उद्देश्य **शासन-परिवर्तन** था—अर्थात शासन की शैली, प्राथमिकताओं और जवाबदेही के ढाँचे में परिवर्तन। वे ऐसी राजनीति की माँग कर रहे थे जो पारदर्शी हो, नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो और

भविष्य-केंद्रित नीतियों पर आधारित हो। इस दृष्टि से 2025 के आंदोलन केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि रचनात्मक और परिवर्तन-उन्मुख थे। जेन Z आंदोलनों ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीति केवल चुनाव और सत्ता-हस्तांतरण तक सीमित नहीं है। उनके लिए लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी, निगरानी और हस्तक्षेप आवश्यक है। इसी कारण आंदोलनों के दौरान "हम केवल विरोध नहीं कर रहे, हम लोकतंत्र का अभ्यास कर रहे हैं" जैसी भावना उभरकर सामने आई। यह दृष्टिकोण पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की सीमाओं को उजागर करता है और सहभागी लोकतंत्र की ओर संकेत करता है। समग्र रूप से, 2025 के जेन Z आंदोलनों की प्रकृति और स्वरूप ने नेपाल की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। बहु-केंद्रित नेतृत्व, डिजिटल और भौतिक सक्रियता का संयोजन, रचनात्मक और डेटा-आधारित विरोध, समावेशी एजेंडा तथा शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ रणनीतियाँ—इन सभी तत्वों ने मिलकर एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया, जो न केवल तत्काल राजनीतिक परिवर्तन का कारण बना, बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए भी एक नया मानक स्थापित कर गया। जेन Z ने यह सिद्ध कर दिया कि युवा आंदोलन केवल असंतोष की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण की सशक्त प्रक्रिया भी हो सकते हैं।

6. डिजिटल मीडिया और वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र

नेपाल में 2025 के जेन Z आंदोलनों की सबसे विशिष्ट और निर्णायक विशेषता डिजिटल मीडिया के माध्यम से एक **वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र** का निर्माण था। जेन Z ने पारंपरिक मीडिया की सीमाओं—जैसे राजनीतिक पक्षधरता, सीमित कवरेज और संपादकीय नियंत्रण—को पहचानते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्मों को राजनीतिक अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक हस्तक्षेप का प्रमुख माध्यम बना लिया। यह वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र केवल सूचना साझा करने का मंच नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा सक्रिय लोकतांत्रिक क्षेत्र बन गया जहाँ सत्ता से प्रश्न पूछे गए, नीतियों की आलोचना हुई और नागरिक सहभागिता को नया अर्थ मिला। लाइव-स्ट्रीमिंग ने इस डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र को वास्तविक समय की शक्ति प्रदान की। धरनों, रैलियों, पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया पर होने लगा। इससे घटनाओं की मध्यस्थता समाप्त हुई और नागरिक स्वयं प्रत्यक्षदर्शी बन गए। लाइव-स्ट्रीमिंग ने न केवल पारदर्शिता बढ़ाई, बल्कि सत्ता की जवाबदेही को भी सुदृढ़ किया, क्योंकि राज्य की प्रत्येक कार्रवाई अब सार्वजनिक निगरानी के दायरे में थी। यह डिजिटल दृश्यता आंदोलन के नैतिक पक्ष को मजबूत करने का माध्यम बनी। फैक्ट-चेकिंग और क्राउड-सोर्स्ड सत्यापन इस वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ थे। अफ़वाहों, भ्रामक सूचनाओं और आधिकारिक बयानों के विरुद्ध युवाओं ने सामूहिक रूप से तथ्यों की जाँच की। विभिन्न स्रोतों से सूचनाएँ एकत्र कर, आँकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण कर और विशेषज्ञ टिप्पणियों को साझा कर, जेन Z ने डिजिटल स्पेस में जिम्मेदार राजनीतिक संवाद की संस्कृति विकसित की। इससे आंदोलन केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया न रहकर तर्कसंगत और विश्वसनीय हस्तक्षेप में परिवर्तित हुआ।

मेम-राजनीति ने डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र को सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक शक्ति प्रदान की। व्यंग्य, हास्य और रचनात्मक दृश्य प्रतीकों के माध्यम से सत्ता और नीतियों की आलोचना की गई। मेम्स ने जटिल राजनीतिक मुद्दों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया और विशेषकर युवाओं के बीच तीव्रता से प्रसारित हुए। इससे राजनीतिक विमर्श अधिक सुलभ और जन-संलग्न बना। मेम-राजनीति ने भय और गंभीरता की जगह आलोचनात्मक हास्य को राजनीतिक हथियार में बदल दिया। नागरिक-पत्रकारिता ने भी डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र को व्यापक बनाया। जेन Z के अनेक सदस्य स्वयं रिपोर्टर, विश्लेषक और टिप्पणीकार के रूप में सामने आए। उन्होंने स्थानीय घटनाओं, प्रशासनिक निर्णयों और आंदोलन की आंतरिक

प्रक्रियाओं को दस्तावेज़ किया। इससे बहु-स्वरीय विमर्श उभरा, जिसमें हाशिए पर मौजूद समूहों की आवाज़ भी शामिल हुई। इस प्रक्रिया ने सूचना के केंद्रीकरण को तोड़ा और लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाया। इस प्रकार, डिजिटल मीडिया ने जेन Z को एक ऐसा वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र निर्मित करने में सक्षम बनाया, जो पारंपरिक मीडिया और राजनीतिक संस्थानों से स्वतंत्र था। यह क्षेत्र आंदोलन की रीढ़ बना, जिसने संगठन, विमर्श और जवाबदेही—तीनों को एक साथ संभव किया।

7. राज्य की प्रतिक्रिया और टकराव

जैसे-जैसे 2025 में जेन Z के आंदोलन व्यापक और प्रभावशाली होते गए, राज्य की प्रतिक्रिया क्रमिक रूप से उपेक्षा से टकराव और दमन की ओर बढ़ती चली गई। प्रारंभिक चरण में सरकार ने आंदोलनों को अस्थायी और सीमित प्रभाव वाला मानते हुए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। यह उपेक्षा स्वयं युवाओं के लिए एक संकेत थी कि सत्ता उनके असंतोष और माँगों को समझने में विफल है। परिणामस्वरूप, आंदोलन और अधिक संगठित तथा मुखर होते चले गए। जब विरोध ने व्यापक जनसमर्थन प्राप्त कर लिया, तब राज्य ने नियंत्रणात्मक उपाय अपनाने शुरू किए। इंटरनेट प्रतिबंध, सोशल मीडिया निगरानी और डिजिटल संचार में व्यवधान जैसे कदम उठाए गए। इन उपायों का उद्देश्य आंदोलनों की गति को धीमा करना और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना था। किंतु इन प्रतिबंधों का प्रभाव उलटा पड़ा। जेन Z ने इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना और आंदोलन को लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संघर्ष के रूप में पुनर्परिभाषित किया। कानूनी धाराओं का प्रयोग और गिरफ़्तारियाँ राज्य की प्रतिक्रिया का अगला चरण रहीं। प्रदर्शनकारियों, डिजिटल एक्टिविस्ट्स और आयोजकों को हिरासत में लिया गया, जिससे भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। परंतु बहु-केंद्रित आंदोलन संरचना के कारण यह रणनीति सफल नहीं हो सकी। किसी एक समूह या व्यक्ति के हटने से आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि नए चेहरे और नेटवर्क उभरते चले गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जेन Z के आंदोलन पारंपरिक दमनात्मक तरीकों के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरोधी हैं।

राज्य और आंदोलन के बीच इस टकराव के दौरान नागरिक समाज की भूमिका निर्णायक हो गई। मानवाधिकार संगठनों, वकीलों, शिक्षाविदों और स्वतंत्र पत्रकारों ने शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज़ उठाई। कानूनी सहायता, सार्वजनिक वक्तव्यों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दों को उठाने से आंदोलनों को नैतिक और संस्थागत समर्थन मिला। इससे सरकार पर दबाव बढ़ा और दमनात्मक कार्रवाइयों की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगे। छात्र-संघों ने भी इस चरण में सक्रिय भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय परिसरों में सभाएँ, बहसें और प्रतीकात्मक विरोध आयोजित किए गए। छात्र-संघों ने युवाओं की ऊर्जा को संगठित रूप प्रदान किया और डिजिटल तथा ऑफ़लाइन आंदोलनों के बीच सेतु का कार्य किया। इसके साथ ही, प्रवासी नेपाली समुदाय ने भी समर्थन बढ़ाया। विदेशों में रहने वाले नेपाली युवाओं ने सोशल मीडिया अभियानों, आर्थिक सहायता और अंतरराष्ट्रीय ध्यानाकर्षण के माध्यम से आंदोलन के दायरे को वैश्विक बना दिया। राज्य की दमनात्मक प्रतिक्रिया और समाज के बढ़ते समर्थन के बीच यह टकराव अंततः राजनीतिक संकट को और गहरा करने का कारण बना। जितना अधिक नियंत्रण और दमन का सहारा लिया गया, उतना ही अधिक आंदोलन व्यापक और वैध प्रतीत होने लगे। इस प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि 2025 का संघर्ष केवल सरकार और युवाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह सत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच टकराव का प्रतीक बन गया। अंततः, राज्य की प्रतिक्रिया और जेन Z आंदोलनों के बीच यह टकराव नेपाल की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इसने यह दिखाया कि डिजिटल युग में दमन से असंतोष दबाया नहीं जा सकता, बल्कि वह और अधिक संगठित तथा व्यापक हो जाता है। यही टकराव आगे चलकर सरकार के पतन और शासन-परिवर्तन की भूमिका तैयार करने में सहायक बना।

8. निर्णायक क्षण: सरकार का पतन (2025)

नेपाल की 2025 की राजनीतिक उथल-पुथल का सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक क्षण वह था जब निरंतर जन-दबाव, व्यापक हड़तालों और राजनीतिक समर्थन के क्षरण के परिणामस्वरूप तत्कालीन सरकार सत्ता से बाहर होने को विवश हुई। यह घटना केवल एक संवैधानिक या संसदीय प्रक्रिया का परिणाम नहीं थी, बल्कि वह **लोकतांत्रिक दबाव की पराकाष्ठा** थी, जिसमें जेन Z एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई। सरकार का यह पतन इस बात का स्पष्ट संकेत था कि लोकतंत्र में सत्ता केवल संख्याबल से नहीं, बल्कि जन-वैधता और नैतिक समर्थन से भी संचालित होती है। 2025 की शुरुआत तक नेपाल में राजनीतिक वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण हो चुका था। महीनों से चल रहे युवा-नेतृत्व वाले विरोध, छात्र आंदोलनों, डिजिटल अभियानों और स्थानीय स्तर पर हो रहे प्रदर्शनों ने शासन की वैधता पर गहरा प्रश्नचिह्न लगा दिया था। जेन Z के आंदोलनों ने सरकार के हर निर्णय, हर वक्तव्य और हर चूक को सार्वजनिक विमर्श का विषय बना दिया। यह निरंतर दबाव केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों, कस्बों और विश्वविद्यालय परिसरों तक फैल गया। इससे सरकार के लिए यह दावा करना कठिन हो गया कि विरोध केवल सीमित शहरी युवाओं तक सीमित है।

जैसे-जैसे आंदोलन व्यापक होता गया, वैसे-वैसे विरोध के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। प्रतीकात्मक विरोध और रैलियों के साथ-साथ **व्यापक हड़तालें** आयोजित की जाने लगीं। परिवहन, शिक्षा संस्थानों, और कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक गतिविधियाँ प्रभावित होने लगीं। इन हड़तालों का उद्देश्य केवल आर्थिक गतिविधियों को बाधित करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि शासन जन-सहयोग के बिना सुचारु रूप से नहीं चल सकता। जेन Z की सक्रिय भागीदारी ने इन हड़तालों को नैतिक वैधता प्रदान की, क्योंकि वे इन्हें स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हथियार के बजाय नागरिक दबाव के साधन के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। इन आंदोलनों की एक विशेषता यह थी कि वे हिंसक टकराव की ओर नहीं बढ़े, बल्कि शांतिपूर्ण दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे। अहिंसक प्रतिरोध ने सरकार के लिए दमनात्मक कार्रवाइयों को वैध ठहराना कठिन बना दिया। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होती, तो वह स्वयं सरकार के लिए जन-आलोचना का कारण बन जाती। इस प्रकार, हर दमनात्मक कदम आंदोलन के नैतिक बल को और अधिक बढ़ाता गया। लगातार जन-दबाव का प्रभाव केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर संसद के भीतर भी दिखाई देने लगा। सरकार के सहयोगी दलों और सांसदों पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बढ़ता दबाव पड़ने लगा। युवा मतदाताओं और नागरिक समाज के संगठनों ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि वे सरकार के साथ खड़े रहते हैं, तो उन्हें राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। इस स्थिति ने गठबंधन राजनीति की कमजोरियों को उजागर कर दिया। जिन दलों ने सत्ता-साझेदारी के लिए सरकार का समर्थन किया था, वे अब अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को लेकर चिंतित होने लगे।

धीरे-धीरे संसदीय सहयोगियों का सरकार से दूरी बनाना शुरू हो गया। कुछ दलों ने सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों की आलोचना की, तो कुछ ने समर्थन "समीक्षा" के नाम पर शर्तों से जोड़ दिया। यह स्पष्ट हो गया कि सरकार के पास अब वह नैतिक और राजनीतिक पूंजी नहीं बची है, जिसके सहारे वह स्थिरता बनाए रख सके। जेन Z के आंदोलनों ने इस प्रक्रिया को तेज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने हर राजनीतिक पैंतरेबाज़ी को सार्वजनिक निगरानी में ला दिया। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि सरकार का पतन केवल संसदीय गणित का परिणाम नहीं था। यद्यपि अंततः सत्ता-परिवर्तन संसद के भीतर हुआ, परंतु उसकी पृष्ठभूमि सड़कों, डिजिटल मंचों और नागरिक समाज में तैयार हुई थी। यदि केवल संख्याबल की बात होती, तो गठबंधन राजनीति के माध्यम से सरकार स्वयं को बचा सकती थी। किंतु जब जन-वैधता समाप्त हो जाती है, तब संख्याएँ भी अपना महत्व खोने लगती हैं। 2025 में यही हुआ—सरकार के पास बहुमत के औपचारिक आंकड़े तो थे, परंतु जन-समर्थन का नैतिक आधार नहीं बचा था। जेन Z की भूमिका इस निर्णायक क्षण में इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने विरोध को केवल "सरकार गिराओ" के नारे तक सीमित नहीं रखा। उनकी माँगें शासन-परिवर्तन पर केंद्रित थीं—अर्थात नीति-निर्माण में पारदर्शिता, युवाओं के लिए अवसर, जवाबदेही और भविष्य-केंद्रित दृष्टि। इस कारण सरकार का पतन किसी अराजक स्थिति में नहीं हुआ, बल्कि एक अपेक्षाकृत संगठित और लोकतांत्रिक संक्रमण के रूप में सामने आया। यह संदेश स्पष्ट था कि सत्ता का परिवर्तन केवल विरोध का अंत नहीं, बल्कि नए राजनीतिक अनुबंध की शुरुआत है।

सरकार के पतन के क्षण में यह भी स्पष्ट हुआ कि जेन Z ने पारंपरिक राजनीतिक शक्ति-संतुलन को बदल दिया है। पहले जहाँ राजनीतिक परिवर्तन का केंद्र संसद और दल हुआ करते थे, वहीं अब सड़क, विश्वविद्यालय परिसर और डिजिटल मंच भी उतने ही प्रभावशाली बन चुके थे। यह एक प्रकार से लोकतंत्र के "केंद्र" के विस्तार का संकेत था, जिसमें नागरिक भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं रही। इस निर्णायक क्षण का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसने भविष्य

की राजनीति के लिए एक नज़ीर स्थापित की। सरकार का पतन यह दिखाता है कि यदि कोई शासन युवाओं की आकांक्षाओं, आर्थिक वास्तविकताओं और सामाजिक न्याय के प्रश्नों की उपेक्षा करता है, तो वह लंबे समय तक टिक नहीं सकता। जेन Z ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल भविष्य के मतदाता नहीं, बल्कि वर्तमान के राजनीतिक अभिनेता हैं। अंततः 2025 में सरकार का पतन नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐसे क्षण के रूप में दर्ज हुआ, जहाँ **लोकतांत्रिक दबाव ने संसदीय संरचना को दिशा दी**। यह पतन न तो सैन्य हस्तक्षेप का परिणाम था, न ही किसी हिंसक विद्रोह का, बल्कि नागरिक चेतना और युवा-शक्ति के संगठित प्रयोग का परिणाम था। जेन Z इस प्रक्रिया की धुरी बनी—एक ऐसी पीढ़ी जिसने शांतिपूर्ण, रचनात्मक और दृढ़ तरीकों से यह दिखा दिया कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। इस प्रकार, 2025 का निर्णायक क्षण केवल सत्ता-परिवर्तन का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह नेपाल के लोकतंत्र के परिपक्व होने का संकेत भी था। यह क्षण यह याद दिलाता है कि जब युवा पीढ़ी स्वयं को "लॉस्ट जेनरेशन" मानने से आगे बढ़कर **"निर्णायक पीढ़ी"** के रूप में संगठित होती है, तो वह न केवल सरकारें बदल सकती है, बल्कि राजनीति के अर्थ और दिशा को भी पुनर्परिभाषित कर सकती है।

9. तात्कालिक परिणाम (Short-Term Consequences)

नेपाल में 2025 में सरकार के पतन के तुरंत बाद जो तात्कालिक परिणाम सामने आए, वे राजनीतिक, प्रशासनिक और वैचारिक—तीनों स्तरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ये परिणाम किसी दीर्घकालिक परिवर्तन की भूमिका मात्र नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वयं में यह स्पष्ट कर दिया कि जेन Z के नेतृत्व में उभरे आंदोलनों ने सत्ता-परिवर्तन के साथ-साथ शासन की प्राथमिकताओं को भी तत्काल प्रभावित किया है। सबसे पहला और प्रत्यक्ष परिणाम **अंतरिम अथवा नई सरकार का गठन** था। सत्ता से बाहर हुई सरकार के स्थान पर जो नई राजनीतिक व्यवस्था सामने आई, उस पर जन-दबाव और युवा अपेक्षाओं की स्पष्ट छाप दिखाई दी। नई सरकार को यह ज्ञात था कि वह केवल संसदीय बहुमत के बल पर नहीं, बल्कि जनता—विशेषतः युवाओं—की निगरानी में कार्य कर रही है। नई सरकार के गठन के साथ ही **युवा-केंद्रित नीति-घोषणाओं** का सिलसिला प्रारंभ हुआ। रोजगार, कौशल विकास, स्टार्ट-अप संस्कृति, डिजिटल शिक्षा और नवाचार जैसे विषय अचानक नीति-विमर्श के केंद्र में आ गए। यह परिवर्तन प्रतीकात्मक भी था और व्यावहारिक भी। प्रतीकात्मक इस अर्थ में कि पहली बार युवाओं की आकांक्षाएँ राजनीतिक घोषणाओं की भाषा में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं, और व्यावहारिक इसलिए कि सरकार को यह संदेश मिल चुका था कि युवाओं की उपेक्षा अब राजनीतिक आत्मघात के समान हो सकती है। इन घोषणाओं के माध्यम से सरकार ने यह संकेत देने का प्रयास किया कि वह केवल संकट-प्रबंधन नहीं कर रही, बल्कि भविष्य-केंद्रित शासन की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

तात्कालिक परिणामों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू **अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता पर पुनर्विचार** के रूप में सामने आया। आंदोलन के दौरान लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंध, सोशल मीडिया निगरानी और कानूनी कार्रवाइयों की व्यापक आलोचना हुई थी। सरकार के पतन के बाद यह स्पष्ट हुआ कि दमनात्मक उपायों ने संकट को सुलझाने के बजाय और गहरा किया। परिणामस्वरूप, नई सत्ता-व्यवस्था को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध और डिजिटल अधिकारों पर पुनर्विचार करना पड़ा। यह पुनर्विचार केवल कानूनी नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी था, जहाँ यह स्वीकार किया गया कि लोकतंत्र में असहमति कोई खतरा नहीं, बल्कि सुधार का अवसर होती है। इसके साथ-साथ **डिजिटल शासन (e-governance)** पर विशेष बल दिया गया। 2025 के आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जेन Z पारदर्शिता, त्वरित संवाद और डेटा-आधारित निर्णयों की अपेक्षा करती है। नई सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता, शिकायत-निवारण तंत्र और नीति-सूचना को सुलभ बनाने की दिशा में कदम उठाने की घोषणा की। यह तात्कालिक प्रतिक्रिया इस बात का संकेत थी कि राज्य अब डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र को केवल चुनौती नहीं, बल्कि शासन के सहयोगी माध्यम के रूप में देखने लगा है। इन सभी तात्कालिक परिणामों को समग्र रूप से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि 2025 के सत्ता-परिवर्तन ने नेपाल की राजनीति में एक **तत्कालिक संवेदनशीलता** पैदा की। सरकार और राजनीतिक दलों को यह अहसास हुआ कि जनता—विशेषतः युवा—अब केवल नीतियों की प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि उनकी निगरानी करने वाली शक्ति भी है। यह संवेदनशीलता आगे चलकर दीर्घकालिक परिवर्तनों की नींव बनी।

10. दीर्घकालिक परिणाम (Long-Term Consequences)

नेपाल में 2025 की राजनीतिक उथल-पुथल के दीर्घकालिक परिणाम तात्कालिक परिवर्तनों से कहीं अधिक गहरे और संरचनात्मक हैं। यदि तात्कालिक परिणाम शासन की दिशा में त्वरित सुधार का संकेत देते हैं, तो दीर्घकालिक परिणाम राजनीति, लोकतंत्र और राज्य-नागरिक संबंधों की मूल अवधारणाओं को पुनर्परिभाषित करते हैं। इन परिणामों का प्रभाव आने वाले वर्षों और दशकों तक नेपाली राजनीति में परिलक्षित होने की संभावना है।

10.1 राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव

सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परिणाम **राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव** के रूप में सामने आया। 2025 के बाद राजनीतिक दलों को यह समझ में आ गया कि यदि वे प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें युवाओं को केवल मतदाता नहीं, बल्कि नेतृत्व के रूप में स्वीकार करना होगा। दलों के भीतर युवा नेतृत्व को स्थान देने, संगठनात्मक संरचनाओं में बदलाव करने और टिकट वितरण में नई पीढ़ी को अवसर देने की प्रक्रिया तेज़ हुई। यह परिवर्तन केवल चेहरों का नहीं, बल्कि राजनीतिक शैली और प्राथमिकताओं का भी था। युवा नेतृत्व अधिक पारदर्शिता, संवाद और डिजिटल सहभागिता पर बल देने लगा, जिससे राजनीति की भाषा और व्यवहार में धीरे-धीरे बदलाव आया।

10.2 लोकतंत्र का पुनर्परिभाषण

दीर्घकालिक परिणामों का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम **लोकतंत्र का पुनर्परिभाषण** है। 2025 के आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह निरंतर भागीदारी और संवाद की मांग करता है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष भागीदारी के नए रूप—जैसे ऑनलाइन परामर्श, सार्वजनिक नीति-चर्चाएँ, ओपन-डेटा पहल और नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र—राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनने लगे। जेन Z ने यह अपेक्षा स्थापित की कि नीतियाँ बंद कमरों में नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से बननी चाहिए। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को अधिक सहभागी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक स्थायी कदम सिद्ध हो सकती है।

10.3 राज्य-नागरिक संबंध

दीर्घकालिक दृष्टि से सबसे गहरा परिवर्तन **राज्य-नागरिक संबंधों** में दिखाई देता है। 2025 से पहले राज्य की प्रवृत्ति अक्सर भय-आधारित नियंत्रण और प्रशासनिक दूरी पर आधारित रही थी। आंदोलनों और सत्ता-परिवर्तन के बाद यह संकेत स्पष्ट हुआ कि यह मॉडल अब टिकाऊ नहीं है। इसके स्थान पर संवाद-आधारित शासन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। नागरिकों को केवल शासित इकाइयों के रूप में नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई। यह परिवर्तन धीमा और संघर्षपूर्ण हो सकता है, परंतु इसके बीज 2025 के अनुभव में स्पष्ट रूप से बो दिए गए हैं। समग्र रूप से, 2025 के बाद के दीर्घकालिक परिणाम यह दर्शाते हैं कि जेन Z का प्रभाव किसी एक सरकार या नीति तक सीमित नहीं है। यह प्रभाव नेपाली लोकतंत्र की संरचना, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाला है। राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव, लोकतंत्र की नई व्याख्या और राज्य-नागरिक संवाद की नई परंपराएँ—ये सभी संकेत देते हैं कि 2025 का आंदोलन एक क्षणिक विद्रोह नहीं, बल्कि एक **पीढ़ीगत लोकतांत्रिक पुनर्गठन** था। यही कारण है कि इसके परिणाम नेपाल की राजनीति में लंबे समय तक गूँजते रहेंगे।

निष्कर्ष (Conclusion)

नेपाल की 2025 की राजनीतिक घटनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि जेन Z अब केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं की दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय और निर्णायक भागीदार बन चुकी है। इस पीढ़ी ने अपने सामाजिक-आर्थिक असंतोष को डिजिटल साधनों, रचनात्मक विरोध और शांतिपूर्ण जन-आंदोलनों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित किया। सरकार का पतन इस तथ्य का प्रमाण है कि पारंपरिक राजनीतिक संरचनाएँ तब तक टिकाऊ नहीं रह सकतीं, जब तक वे युवाओं की आकांक्षाओं, रोजगार-सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही की माँगों को गंभीरता से संबोधित न करें। दीर्घकालिक दृष्टि से, यह आंदोलन नेपाल के लोकतंत्र के लिए चेतावनी और अवसर—दोनों है। चेतावनी इसलिए कि शासन-विफलता और युवा-

उपेक्षा राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकती है; और अवसर इसलिए कि जेन Z की भागीदारी लोकतंत्र को अधिक समावेशी, सहभागी और उत्तरदायी बना सकती है। इस प्रकार, 2025 का नेपाली अनुभव यह दर्शाता है कि भविष्य की राजनीति का स्वरूप युवा-केंद्रित, डिजिटल-सक्षम और नैतिक अपेक्षाओं से युक्त होगा।

संदर्भ-सूची

[1]. Barber, B. R. (2003). *Strong democracy: Participatory politics for a new age*. University of California Press.
[2]. Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action*. Cambridge University Press.
[3]. Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope*. Polity Press.
[4]. Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
[5]. Diamond, L. (2019). *Ill winds: Saving democracy from Russian rage, Chinese ambition, and American complacency*. Penguin.
[6]. Gurr, T. R. (1970). *Why men rebel*. Princeton University Press.
[7]. Henn, M., Weinstein, M., & Wring, D. (2002). *A generation apart? Youth and political participation*. British Journal of Politics.
[8]. Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, cultural change, and democracy*. Cambridge University Press.
[9]. Jenkins, H. (2006). *Convergence culture*. New York University Press.
[10]. Kymlicka, W. (2001). *Politics in the vernacular*. Oxford University Press.
[11]. Norris, P. (2011). *Democratic deficit*. Cambridge University Press.
[12]. Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone*. Simon & Schuster.
[13]. Robertson, R. (1995). *Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity*. Sage.
[14]. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
[15]. Shah, D. V., et al. (2005). Youth, civic engagement and digital media. *Journal of Communication*, 55(3).
[16]. Tilly, C. (2004). *Social movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
[17]. Touraine, A. (1985). *An introduction to the study of social movements*. Sage.
[18]. UNDP. (2018). *Youth and democratic participation*. United Nations.
[19]. Van Dijk, J. (2012). *The network society*. Sage.
[20]. Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. (1995). *Voice and equality*. Harvard University Press.
[21]. Weiss, J. (2020). Generation Z and political change. *Global Youth Studies*.
[22]. World Bank. (2020). *Youth employment and political stability*. World Bank Publications.
[23]. Yates, L. (2015). Rethinking prefiguration. *Social Movement Studies*, 14(1).
[24]. Youth Studies Network. (2019). *Digital activism and youth movements*. Routledge.
[25]. Zukin, C., et al. (2006). *A new engagement? Political participation and civic life*. Oxford University Press.